

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं चुनौतियों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. गजेन्द्र सिंह राठौड़

सहायक प्रोफेसर (भूगोल), भूगोल विभाग
श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मिश्र महिला महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू), राजस्थान
rathoregajendra806@Gmail.com

प्रस्तावना:- समाज शिक्षा द्वारा नवयुवकों के विचार और भावना में वे सभी विशिष्टताएं समाहित की जा सकती हैं जिनके सहारे उन्हें अपने और अपने देश के गौरव तथा आत्म सम्मान का बोध हो सके। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। हर समाज के जीवन की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। उन जीवन की आवश्यकताओं के द्वारा जीवन का आदर्श बनता है। जीवन के आदर्श द्वारा हमारा जीवन उद्देश्य निश्चित होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति में हम कुछ बिन्दु निश्चित करते हैं। इन बिन्दुओं पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास टिक जाते हैं। यही बिन्दु हमारे मान बिन्दु होते हैं यही जीवन मूल्य है। इन मूल्यों की प्राप्ति में शिक्षा का बहुत योगदान होता है।

शिक्षा जो कि मानव जीवन का आधार स्तम्भ है, के अभाव में मानव जीवन के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह मानव जीवन की उत्कृष्टता एवं उच्चता का प्रतीक है। प्राचीनकाल से ही शिक्षा को आत्मज्ञान एवं आत्म प्रकाश का साधन माना गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है। वर्तमान में शिक्षा जहाँ एक ओर बालको का सर्वांगीण विकास के लिए भी एक आवश्यक एवं शक्तिशाली साधन है। यह आगे आनी वाली पीढ़ी को उच्च आदर्शों आकांक्षाओं विश्वासों जैसे सांस्कृतिक सम्पत्ति को हस्तान्तरित करता है। बालक की वैयक्तिक प्रगति, उसका मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा के वाछंतीय उद्देश्य :- भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को अनेक शिक्षाविदों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनमें से दो अत्यन्त महत्वपूर्ण मतों की ओर अनायास ही हमारा ध्यान जाता है।

प्रथम भारत के भूतपूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन का और दूसरा संयुक्त राष्ट्रसंघ के उपनिदेशक डा. मेलकौम एस. आदिशेशैया का सन् 1900 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में अपने ओजस्वी भाषण के अन्तिम अनुच्छेद में लॉर्ड कर्जन ने गणना की थी।

“जहाँ तक मेरी राय का प्रश्न है यदि कभी मैंने यह पाया कि उच्च शिक्षा भारत में संतोषजनक परिणाम उत्पन्न नहीं कर रही है तो मैं आपकी परीक्षाओं का बहिष्कार करने आपके उपाधि-पत्रों को जला डालने तथा किसी पुरानी किश्ती में आपके सारे प्राध्यापकों, सिन्डीकेट, सीनेट, उपकुलपति और यहाँ तक कि कुलपति को भी बिठाकर बंगाल की खाड़ी में डूबों देने के लिए तैयार हो जाना चाहूंगा। बाबा आदम के जमाने की ओर लौट जाना ही उत्तम होगा बजाय इसके कि एक मिश्रित या संकर-नैतिकता को उत्पन्न किया जाए या एक अवैध सभ्यता को पोषित किया जाए।

नई दिल्ली की एक सभा में 13 जनवरी 1969 को भाषण देते हुए डॉ. मेलकोम एस. आदिशेशैया ने स्पष्ट शब्दों में कहा था -

“भारतीय विश्वविद्यालय बौद्धिकता विरोधी दुर्गों के बाहर की ओर झुके झरोखे या ऐसे विशाल मंहगे व अकुशल कारखाने बनते जा रहे हैं जो कि बुद्धिजीवी के स्थान पर उनकी नकल करने वाले व्यक्तियों को तैयार कर तैयार माल के रूप में

निकाल रहे हैं। उनके पढ़ाने की विधियाँ एक पक्षीय, अधिकारवादी ढंगी पद्धतियाँ हैं। उनके पढ़ाने की रीतियाँ कण्ठस्थ याद करने या रटने की हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी सूचना व ज्ञान के टुकड़ों व भागों को ग्रहण किया जा सके। जो कुछ वहाँ पढ़ाया या सीखा जाता है। उसका कलाओं की अवस्था देश के विकास की मांगों या रोजगार के अवसरों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसकी परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन नहीं करती। यह एक विशालकाय अमानवीय मांस को कुचलने पीसने की मशीन है जो नकली खाद्य पदार्थों को अपने दाँतों से काट काटकर अलग अलग अर्धहीन समूहों में विभाजित कर देती है। यह एक साधन सम्पन्न धोखे का आह्वान अथवा निरर्थक रूप से की जा रही चालाकी का एक प्रदर्शन मात्र ही है।

जब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश भारत में लागू की गई थी तो उसका लक्ष्य, जैसा कि सर्वविदित ही है, अंग्रेजी शासकों के उद्देश्यों की पूर्ति करना ही रखा गया था, यथा, ऐसे भारतीय तैयार करना जो अल्प वेतनजीवी लेखक (क्लर्क) बनकर अंग्रेज कार्यलयों व प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकें तथा जन्म या रंगरूप से भारतीय होने पर भी अपनी रुचियों, खान-पान, वेश-भूषा आदि में अंग्रेजियत के रंग में रंगे हों। अंग्रेज विशाल भारतीय जनता को शिक्षित करने या उसका जीवन-स्तर उँचा उठाने में रुचि नहीं रखते थे, वे तो बस समाज के कुछ उच्च अभिजात वर्ग को पहले अपने रंग में रंगना चाहते थे, और यह आशा करते थे यह प्रभाव शनैः-शनैः नीचे के वर्गों व समूहों में भी बहता या छनता हुआ चला जाएगा, जैसा कि उनके निम्नगामी निस्पंदन सिद्धान्त (Downwards filtration theory) से प्रकट होता है।

लेकिन वर्तमान भारतीय संदर्भ और ब्रिटिशकालीन भारत के सामाजिक संदर्भ में तो जमीन आसमान का अन्तर हो चुका है। अब भारतीय समाज एक प्रजातन्त्रीय समाज है। हमारे देश का लोककल्याणकारी राज्य सभी वर्गों व जन-समूहों की शिक्षा, कल्याण व उन्नति में रुचि रखता है। आज वह आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण तथा चहुँमुखी प्रगति की दिशाओं में अग्रसर होने के लिए कृत-संकल्प है। यह ऐसा समाज है जिसमें आज भी अशिक्षितों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है, जिसमें परम्परागत मूल्यों का विघटन हो रहा है तथा परम्परागत व आधुनिक मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं, प्रकार्यों आदि में संघर्ष छिड़ा हुआ है।

जिस देश में ऐसा सामाजिक संदर्भ हो, वहाँ की उच्च शिक्षा के लक्ष्यों का आदर्श प्रतिरूप (Ideal Type) तो यही होना चाहिए कि वह स्वतंत्र हो, स्वतंत्र चिन्तन को प्रोत्साहन दे तथा समाज की मांगों के अनुसार हो। शिक्षा-प्रणाली के स्वतंत्र होने से हमारा तात्पर्य यह है कि वह किन्हीं सीमित या संकुचित लक्ष्यों को लेकर न चले तथा स्वार्थी व्यक्तियों या उनके समूहों (Interest Group) के हाथों की कठपूतली न बनी रहे। शिक्षा केवल नगरों के मध्यम व उच्च वर्गों के सम्पन्न परिवारों अथवा प्रभावी राजनीतिज्ञों की ही विशेषाधिकार न बनी रहे, अपितु उसका लाभ देश के सभी वर्गों तक पहुँचे, चाहे वे वर्ग ग्रामों के हो अथवा नगरों या कस्बों के तथा चाहे वे किसी भी धर्म, मत या राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो। उच्च-शिक्षा-संस्थाओं में जिन लोगो की पहुँच नहीं हो पाई उन बूढ़े, प्रौढ़, ग्रामीण किसानों, दस्तकारों, दूकानदारों व सामान्य नागरिकों को भी देश की उच्च शिक्षा-संस्थाओं के शिक्षण एवं शोध कार्य से लाभ मिलना चाहिए जिससे उनके ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो सके तथा वे अपने जीवन के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तरों को उँचा उठा सकें। किसी रूप में उनका भी उच्च शिक्षा से सम्बन्ध बना रहना चाहिए जिससे उन्हें अपनी व्यवसाय-कुशलता व उत्पादन के लक्ष्यों को उन्नत करने सहायता मिले। इसका अर्थ यही हुआ कि वह उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवलमात्र व्यक्तिगत रूप से सामाजिक गतिशीलता, समृद्धि, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परिवर्तन या विकास करने का सयन्त्र मात्र न हो वरन सम्पूर्ण समाज को प्रभावित या लाभान्वित करने में समर्थ हो।

भारतीय उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ :-

भारतीय मनीषियों ने कहा है। सा विद्या या शारिन्त। अर्थात जो हमे अनुशासित करती है। पुनः वे कहते है- सा विद्याया विमुक्तये यानी वही विद्या है जो हमे मुक्ति देती है मुक्ति संकीर्णता से वायदीप भौतिकता की परिधि से गुरुग्रंथ साहिब में भी वर्णित है विद्या विचारी परोपकारी बदलती व्यवस्था के परिपेक्ष्य में हमारी नैतिकता गुणवत्तापूर्ण व व्यक्तित्व निर्माण के दिन शिक्षा पदति कहां तक अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ है विचारणीय प्रश्न है, भूमण्डलीकरण के इस दौर में हम अपने ही पहचान खोते जा रहे है पूरे विश्व में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके तीन घटक है छात्र, अध्यापक और अभिभावक। इन तीनों के समन्वय के बगैर शैक्षणिक त्रिभुज के निर्माण की परिकल्पना ही बेमानी है।

विद्यालयी पढाई करने वाले नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज पहुँच पाता है उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वालों का अनुपात हमारे यहां दुनिया में सबसे कम 11% है जबकि अमेरिका में यह 83% है इस अनुपात को 15% तक ले जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत को 2,26,410 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

हमारे यहाँ चारों तरफ अनास्था का महौल पनप रहा है गुरु शिष्य का संबंध का धनत्व घट रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। बकौल भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव अशोक टाकुर शोध पर 0.8% खर्च हो रहा है जबकि कम से कम 02% खर्च होना चाहिए। रक्षा और अन्य मंत्रालयों का बजट लम्बा चौड़ा होता है पर शिक्षा की अनदेखी होती है समय पर प्राध्यापकों को वेतन नहीं मिलना, फलतः हड़ताले संस्कृति विकसित होती चली जा रही है। जिसका खामियाजा अनन्त छात्रों को भुगतना पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय की जगह भारत सरकार ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRDD) कहना शुरू कर दिया है ब्रिटेन में इसे शिक्षा और कौशल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा रोजगार व कार्यस्थल संबंध मंत्रालय कहा जाता है जब पुरी दुनिया में विद्यालय की कल्पना नहीं की थी उस वक्त हमारे यहां विश्वविद्यालय हुआ करते थे विश्वस्तरीय नालंदा विश्व विद्यालय तक्षशिला विश्व विद्यालय विक्रमशिला विश्व विद्यालय की पावन धरती पर शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां कही न कही बहुत कचोटती है शिक्षा में जब सियासत की गैर जरूरी घटिया दखलंदाजी बढ़ती है तो बेवजह शिक्षा जगत को शर्मसार होना पड़ता है किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है-सियासत दानों को हम आदमी समझे तो क्यों समझें सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती।

उच्च शिक्षा पर बहस तब बेमतलब लगने लगती है जब यह तथ्य जेहन में उभरता है कि तीन साल पहले बिहार के विश्व विद्यालयों में एक ही जाति के छः कुलपति नियुक्त थे कुछ साल पहले पांडिचेरी के शिक्षा मंत्री के स्थान पर कोई अन्य विद्यार्थी उनके लिए माध्यमिक परीक्षा दे रहा था ऐसे में उच्च शिक्षा में सुधार की संभावना को आघात लगता है।

इतना ही नहीं राज्यों में सरकारें बदलती हैं तो विभिन्न पार्टियां अपने घोषणा-पत्र के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम भी बदलते हैं ऐसे में विद्यार्थियों के सामने संकट पैदा होता है कि वो वामपंथ की ओर जाये या दक्षिणपंथ की ओर या किसी मध्यम मार्ग की ओर। राजस्थान में जब एक खास दल की सरकार आती है, तो वहां इतिहास के पाठ्यक्रम में दो पन्ने जोड़ दिये जाते हैं और जब दूसरी पार्टी सत्ता संभालती है तो उन दो पृष्ठों की फाड़कर हटा दिया जाता है यह हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतीकरण का दुर्भाग्यपूर्ण मौजूदा सच है।

इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है इनमें से 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच की है। यदि इन्हे ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाये तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं।

योजना आयोग के सदस्य (नीति आयोग) और पुणे वि.वि. के पूर्व उप कुलपति नरेन्द्र जाधव चकित है कि कई विश्व विद्यालयों में 30 सालों से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है पुराना पाठ्यक्रम और जमीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी है।

उच्च शिक्षा की सर्व प्रमुख चुनौती है सभी प्रदेशों में एक समान शिक्षा नीति का न होना। हालांकि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत रखा गया है और राज्यों पर कोई भी पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा थोपा नहीं जा सकता। पर परस्पर समन्वय स्थापित कर एक सम्यक समावेशी सुदृढ़ समग्र और संतुलित पाठ्यक्रम का ढांचा सामने रखा जा सकता है। कई विद्वानों का तर्क है कि जब इस सम्पूर्ण देश का राष्ट्रगान एक है राष्ट्रीय गीत एक है राष्ट्रीय चिन्ह एक है। एक राष्ट्रीय पक्षी है, तो एक शिक्षा पद्धति क्यों नहीं। सच्चे युगदृष्टा डॉ. लोहिया ने कितना सटीक कहा था—

राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान
बिडला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान।

उपसंहार :-

अधिकांश भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं का यह यथार्थ समाजशास्त्रीय चित्रण हमारी सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं का ही स्पष्ट प्रतिबिम्ब व विस्तार कहा जा सकता है। यह निस्संदेह खेद का विषय है कि जहाँ उच्च शिक्षा को हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त विविध सामाजिक व सांस्कृतिक विडम्बनाओं, सामाजिक व्याधि तथा प्रथक्कत्व, निराशा, प्रतिमानहीनता आदि को कम करने तथा देश में स्वस्थ प्रकार के सामाजिक परिवर्तन युग का सूत्रपात करना चाहिए था, वहाँ इसने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी हमारी नई पीढ़ी में बौद्धिक दासता तथा अन्य बुराइयों को प्रश्रय दिया है। इसका दोष किसी एक शिक्षामंत्री, उपकुलपति, शिक्षक, विद्यार्थी, संरक्षक या राजनीतिज्ञ के सिर पर ही नहीं मढ़ा जा सकता। सभी ने अपनी अपनी पृष्ठभूमियों, अभिरूचियों तथा सामर्थ्य के अनुसार स्थिति को बिगाड़ने में योग दिया है। अतः यदि इस स्थिति को सुधारना है तो इनमें इन सभी सन्दर्भ समूहों का सही योगदान अत्यावश्यक है।

संदर्भ सूची :

- [1]. डॉ. सत्यपाल रूहेला, भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- [2]. लक्षता गुप्ता, भारतीय समाज और शिक्षा विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी।
- [3]. सचदेवा यादव, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा, विजया पब्लिकेशन लुधियाना।
- [4]. एन.एस.बक्शी, उदीयमान भारतीय समाज एवं शिक्षा, प्रेरणा पब्लिकेशन, दिल्ली।
- [5]. डॉ. गुरसनदास त्यागी, डॉ. विजय कुमार नन्द उदीयमान भारत में शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2
- [6]. एम.एस. सचदेवा, के.के. शर्मा, शिवानी बिदल, पी.के. साहू उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अभिषेक ऑफसेट प्रिन्टर्स मॅरठ(यू.पी.)
- [7]. अन्य स्रोत समसामयिकी पत्र पत्रिकाएँ।